गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जिन चार मामलों की जांच केन्द्रीय जांच आयोग ने की थी, उनमें से तीन पर अभी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Commercial Credit Offer by E.N.I.

*478. **Shri Braj Behari Mehrotra:**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nearly two-thirds of the $100 million commercial credit offered by the Italian State-owned oil firm E.N.I. some years ago has been allowed to lapse; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Yes, Sir.

(b) The lapse was unfortunate since Government was not aware till December, 1965 that the Italian Government had not extended the licence given to E.N.I. for operating this credit beyond 31st December, 1966.

दिल्ली पुलिस की शिकायतें

*479. **श्री शिंकरे :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों को सर्दी, गर्मी तथा वर्षा ऋतुओं के लिये पूरी वर्दियां नहीं दी जाती हैं, यद्यपि उन्हें चौबीस घण्टे ड्यूटी पर रहना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल थोड़े से ही कांस्टेबल को रिहायशी क्वार्टर दिये जाते हैं और वह भी थोड़ी अवधि के लिये ही;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को गजेटिड छुट्टियों में भी न तो कोई छुट्टियां ही मिलती हैं और न ही उनको कोई समयोपरि भत्ता दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों को वर्दी की चीजें विभिन्न पदों तथा विशिष्ट कर्त्तव्यों के लिये पंजाब पुलिस नियमों के अनुसार दी जाती हैं ।

(ख) रिहायश की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये आगामी 24 महीनों में व्यय किये जाने के लिये 50,00,000 रु० लागत का निवास-स्थान बनाने का एक जबर्दस्त कार्यक्रम अभी हाल ही में स्वीकार किया गया है । पुलिस कर्मचारियों को निवासस्थान देने के लिये समय की किसी सीमा की कोई शर्त नहीं है ।

(ग) दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को कोई समयोपरि भत्ता पाने का अधिकार नहीं है । जब कभी लगातार 9 घण्टे से अधिक समय की ड्यूटी लगती है तब या तो उनके खाने की व्यवस्था और जहां कहीं उसकी सुविधा न हो वहां ज्यादा से ज्यादा 1.25 रु० तक प्रतिदिन के हिसाब से लोक सेवा की अनिवार्यता के विचार से देने की मंजूरी दी गई है । जहां तक राजपत्रित छुट्टियों का प्रश्न है, कांस्टेबलों के बड़े भाग को इस प्रकार की छुट्टी देना सम्भव नहीं है । छुट्टियों के दिनों पर भारी व्यवस्था-कार्य करना होता है क्योंकि ये छुट्टियां राष्ट्रीय/धार्मिक उत्सव या अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के दिनों पर पड़ती हैं । किन्तु कार्यपालक कर्मचारियों को वर्ष में 15 दिन

का और दिल्ली प्रशासन के अन्य कर्मचारियों को 12 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है ।

(घ) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के काम और रहन-सहन की स्थिति की जांच करने के लिए सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया है ।

Superannuation

2088. Shrimati Ramdulari Sinha: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the broad principles which have been laid down about the extension or re-employment of superannuated officers?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-7393/66].

Use of Malayalam in Kerala

2089. Shri Vasudevan Nair:
Shri Warior:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the special officer appointed for the introduction of Malayalam in Kerala has submitted any report; and

(b) whether it is a fact that even now replies to representations in Malayalam are being sent in English?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Orders were issued by the State Government in October, 1965 that communications received in the Malayalam language should be replied to in the same language. No instances of non-observance of these orders have come to the notice of the State Government.

महाराष्ट्र में डाकघर

2090. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 में महाराष्ट्र में कितने उप-डाकघरों को मुख्य डाकघर तथा शाखा डाकघर बनाने का विचार है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): 1966-67 के दौरान किसी भी उप डाकघर को प्रधान डाकघर में बदलने का प्रस्ताव नहीं है । किन्तु इसी अवधि में एक उप डाकघर को शाखा डाकघर में बदलने का प्रस्ताव है । इसके अलावा, 1966-67 के दौरान दो उप डाकघरों को शाखा डाकघरों में पहले ही बदला जा चुका है ।

डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2091. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 30 जून, 1966 तक कितने डाक तथा तार कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये ; और

(ख) क्या 1966-67 में उस राज्य में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 2485 ।

(ख) जी हां । 62 यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से कर्मचारियों के क्वार्टरों की 10 यूनिटें निर्माणाधीन हैं ।

महाराष्ट्र में किराये की इमारतों में डाकघर

2092. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1966 को महाराष्ट्र में कितने डाकघर किराये की इमारतों में काम कर रहे थे ;